# 'राजस्थान मंडपम से मिलेगी प्रदेश को नई पहचान, प्रदेश में बढ़ेगा 'कॉन्फ्रैंस टूरिज्म''

## होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित की जाएं सुविधाएं- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 17 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार औद्योगिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी, ताकि प्रदेश बड़े-बड़े आयोजनों के लिए पहली पसंद बने और यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम की कार्ययोजना के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में होलिस्टिक अप्रोच के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की पुख्ता कार्ययोजना बनाई जाए ताकि यहां पर छोटे से लेकर बड़े प्रकार के आयोजन सुगमता से हो सके।

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम की कार्ययोजना के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया।*

- भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान मंडपम के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक ली और कहा कि इससे प्रदेश को 350 बिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास के साथ विरासत भी' के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मण्डपम में प्रदेश के हैरिटेज के साथ हाईटैक सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, जिससे यह स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आकर्षण केन्द्र भी बने। बैठक में उन्होंने कन्वेंशन सेन्टर, एग्ज़ीबिशन सेन्टर, मीटिंग हॉल एवं आगन्तुकों के लिए पार्किंग सुविधाओं को विकसित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में राजस्थान मंडपम के निर्माण की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता व रीको के वरिष्ठ अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

## तेलंगाना में ओबीसी का आरक्षण 23 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हुआ

हैदराबाद, 17 मार्च। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा एलान किया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा किराज्य में शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जो अब तक 23 प्रतिशत था।

- तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी ने कहा कि राज्य में शिक्षा, नौकरी, रोजगार व राजनीति में ओबीसी समुदायों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36 प्रतिशत है। अब हम शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं।

# 'संसद में मंत्रियों ने दिए 1300 आश्वासन, एक भी पूरा नहीं किया'

## संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा लोकसभा में दिए गए 547 व राज्यसभा में दिए गए 764 आश्वासन पूरे नहीं हो सके

नयी दिल्ली, 17 मार्च। संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा सदस्यों को उनके प्रश्नों तथा अन्य वक्तव्यों के जवाब में दिये गये कुल आश्वासनों में से 1300 से अधिक अभी भी लंबित हैं और पूरे नहीं किये गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि लोकसभा में 547 और राज्यसभा में 764 आश्वासन पूरे नहीं किये जा सके हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल पूछते हुए कहा था कि वर्ष 2024 में मंत्रियों ने राज्यसभा में सदस्यों को 160 आश्वासन दिये थे, जिनमें से केवल 41 ही पूरे किये गये हैं और 119 अभी भी लंबित हैं।

इसके जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरूगन ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने वर्ष 2018 में आनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की थी। इसके बाद से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी आश्वासनों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा सदस्यों को लाखों आश्वासन दिये गये हैं और इन्हें पूरा भी किया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये 99 प्रतिशत आश्वासनों को पूरा किया गया है। मुरूगन ने कहा कि कुछ आश्वासनों से संबंधित कार्य ऐसी परियोजनाओं के होते हैं, जिन्हें पूरा होने में समय लगता है। इसके बारे में निरंतर जानकारी हासिल की जाती है और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाती है।

- आप नेता संजय सिंह ने बताया 2024 में मंत्रियों ने 160 आश्वासन दिए थे मात्र 41 ही पूरे किए गए हैं 119 अभी भी लंबित हैं।

इस पर आम आदमी पार्टी के सदस्य ने कहा कि मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों और मंत्रालय की वेबसाइट पर दिये गये आंकड़ों में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि मंत्री वर्ष 2024 से संबंधित आंकड़ों पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाब में कहा जा रहा है कि 99 प्रतिशत आश्वासन पूरे किये गये हैं, जबकि मंत्रालय की वेबसाइट कह रही है कि संसद के दोनों सदनों में 1300 से अधिक आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में 547 और राज्यसभा में 764 आश्वासन पूरे नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय होता है। उन्होंने कहा कि इन पर नजर रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली भी है और एक समिति भी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जब सदस्य किसी संबंध में मंत्री या विभागों को कोई पत्र लिखते हैं तो उसका भी जवाब एक महीने में दिया जाना चाहिए।

## प्र.मंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड को महाकुंभ का जल भेंट किया

नई दिल्ली, 17 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड से मुलाकात की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से लाया गए पवित्र जल (जल) से भरा एक कलश भेंट किया। तुलसी गबार्ड ने मोदी को एक माला भेंट की।

गबार्ड कई देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में भारत पहुंची हैं। उनकी एशिया यात्रा का समापन 18 मार्च को दिल्ली

- अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड एशिया यात्रा के तहत भारत आईं हैं और रायसीना डायलॉग में भाषण के साथ उनकी एशिया यात्रा का समापन होगा।

में रायसीना डायलॉग में भाषण देने के साथ होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया था।रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा किया जा रहा है।

गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई।

# सीएजी की नियुक्ति सम्बंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस दिया

## एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है

नयी दिल्ली, 17 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री द्वारा करने की मौजूदा प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही पीठ ने इसे इसी मुद्दे पर लंबित अन्य मामले के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाले महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीएजी द्वारा ऑडिट को रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में सीएजी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। भूषण ने तर्क दिया कि यहां सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है।

पीठ ने उनसे हाल के वर्षों में सीएजी की स्वतंत्रता पर संदेह करने से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा।

- याचिका में सीएजी की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा करने को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।

भूषण ने तर्क दिया कि सीएजी की रिपोर्टों की संख्या कम हो गई है और कर्मचारियों की संख्या घट रही है।

उन्होंने आगे दलील दी कि अदालत ने पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के संबंध में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अधिवक्ता भूषण ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सीएजी के लिए भी इसी तरह के निर्देश आवश्यक हैं। पीठ ने अनुच्छेद 148 का हवाला देते हुए कहा, हमें अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा करना होगा, पीठ ने कहा कि सीएजी को पद से हटाने के संबंध में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है।

पीठ ने हालांकि आखिरकार मामले की जांच करने का फैसला किया।

## विश्व टॉप ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अहमबाद 27 वें और आईआईएम बैंगलोर 40 वें नम्बर पर है। आईआईटी मद्रास पैट्रोलियम इंजीनियरिंग में 31 वें नम्बर पर है वहीं डवलपमैंटल स्टडीज़ में जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी (जेएनयू) 29 वें स्थान पर है। क्यू एस वर्ल्ड टॉप रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण रुझान नज़र आता है कि वो है एशियन युनिवर्सिटीज़ का उदय। इसमें चीन व सिंगापुर सबसे आगे हैं। भारत ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इन संस्थाओं ने रिसर्च के क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर विश्वस्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। हालांकि भारतीय विश्वविद्यालयों को अभी फैकल्टी -विद्यार्थी अनुपात, रिसर्च फंडिग व वैश्विक दृष्टिकोण के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी रैंकिंग प्रभावित होती है।

## 'सैन्ट्रल स्कूल...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भारत के नेता के रूप में भी उभरकर आये हैं, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत परिसीमन और भाषा के मुद्दे पर संगठित हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इन दोनों मुद्दों को एक ऐसे रूप में पेश किया है जिससे लगता है कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत के "आक्रामक, अड़ियल और निरंकुश" रुख का शिकार बन रहा है तथा दक्षिण भारत को उसके उचित अधिकारों तथा फण्ड्स से वंचित किया जा रहा है, जो उसका न्याय सम्मत अधिकार है। दक्षिण भारत का जनसामान्य यह बात पहले ही मानकर चल रहा है कि दक्षिण भारत की आमदनी ज्यादा है तथा वह राष्ट्रीय राजस्व में भी ज्यादा योगदान दे रहा है, लेकिन उसे केन्द्र सरकार से बदले में बहुत राशि मिल रही है। केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने इस बिन्दु को इस रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किया था, उसके बाद दक्षिण भारत के एक के बाद एक- सभी नेताओं ने जनसामान्य तक यह बात इस रूप में पहुँचाई है।


शोक संदेश

अत्यंत दुःख के साथ सूचित कर रहे हैं कि
हमारी पूजनीय माता जी

श्रीमती रामपति देवी जी

(प्रधान, पंचायत समिति, मासलपुर, जिला-करौली)

का देवलोक गमन
दिनांक 16 मार्च को हो गया है!

तीये की बैठक

18 मार्च, 2025 (मंगलवार)

निज निवास, बड़ागांव खेड़ला,
तहसील - महवा, जिला - दौसा

शोकाकुल परिवार

राजाराम गुर्जर
पुत्र (पूर्व सभापति, करौली)

डॉ. सौम्या गुर्जर
पुत्रवधू (महापौर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर)
एवं समस्त परिवारजन

संपर्क 9799908131, 9461585400
8875727341, 9414335672

SCAN FOR THE LOCATION


राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908